

हवा-पानी की आग़ादी के बिना आग़ादी अदूरी

ललित गर्ग

देश एवं दुनिया के सामने स्वच्छ जल एवं जलहीन प्रदूषण को ममत्या कंपीर में गम्भीर होती जा रही है। मुद्द इवा एवं पीये के स्वच्छ जल की मिलन र घटाती मात्रा को लेकर बड़े सतते सुधे है। घरती पर जीवन के लिये जल एवं जल सबसे जरूरी वस्तु है, जल एवं जल ही तो जीवन है। जल एवं जल ही किसी भी प्रकार के जीवन और उसके अस्तित्व को सम्पर्क बनाता है। जीवन के तीन आधार तत्व हैं- जल, पानी और धरती हैं। इनको संरक्षा न केवल हमारी अस्तित्व-निर्भरता में बुझी है, बल्कि मानवता की ऐतिहासिक विमोदरी भी है। आज का युग, जिस तरंगे में विकसित हो रहा है, उसी भागदीढ़ में इन और पानी को परम स्वाधीनता से वर्चित कर रहा है। रूप-योजना युद्ध, दिल्ली का उच्च प्रदूषण सूचकांक, अमेरिका के जंगलों की धूए में गंदलों जल, बहुता यहान प्रदूषण-ये सब संकेत देते हैं कि जल में आजानी मरलव 'स्वस्थ जल' पाया है। हमारे -आजानी- को नया अर्थ नहिं तो यह प्राकृतिक संसाधनों यानी जल एवं पानी की आजानी पर भी निर्भर है, जो मानव व पर्यावरण-जगत दोनों के लिए जीवनदायिनी है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल रुजनीतिक बंधनों में मुक्त नहीं है, बल्कि जीवन के

सम्पादकांग...

वाट को आजादी

आजाद भारत न अमन लगा का मब्द बराकमतों चाल क्या दे है? किमी पे भी पूछ जाए तो जवाब होगा, बोट। हम अधिकतर भासतेहों को आजादी के 78 माल बद भी न काम का रोजगार दे सके, न मकान दे सके, न ही बच्चों के लिए सड़े रिश्वा हो दे सके। कद्यों को तो ऐटी, कमज़ू और मकान की भी समस्या लही हो ले-देकर उनके पास उनका बेटा है जो उन्हें हीमयत देता है, पहचान देता है, महल्ल देता है और जो उन्हें पाच माल के बाद बदला लेने की ज़क्र देता है। इसी उक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने इदिया गांधी से एपर्मेंटी का बदला लिया, पर जमना पट्टी की माफकर की नालायकों को दखले हुए इदिया गांधी को छिपा दी। यूपीए की मस्कर के खण्डनाचार की मना दी गई और पिछले लोकमानों के चुनावों में भाजपा को बहुमत ये नीचे ला कर उन्हें भी बता दिया कि केकल आकारिक नहीं मैं ही ऐट नहीं भरता। अगर लोगों में कट जाओगे तो क्षीमत चक्कानी पलेंगे। अपील लोग तो अधिकतर घरों में ही नहीं निकलते जबकि चुनावों के पास भागे मतदान होता है। चाहे बड़ी मछली में बह अशिक्षित हो, पर बोट की कौमता बह जाती है। उनके लिए यह सशक्तिकरण का उपकरण है। उत्तर एिझी के बोल्ड मौलाम्बूर मार्केट में काम कर रहे बिहार के अरसिया निले के मुकाबले गुन का कहना है कि वह भर केकल दे बार नाता है, छठ पूजा और चुनाव के लिए। वह कहता है कि बोट देना जल्दी है। उसमें आप सिस्टम में खड़े हो। जो गरीब है, वहिस है, समाज की मबद्दी नीचे के पायदान पर खड़े है (और दुनिया की चीजों में बड़ी अवृद्धिकरण में ऐसा लोग भरे हुए है) वह ममझे है कि शायक और ऊपीढ़क वर्ग से जबक्केहों के लिए बोट ही उनके पास एकमात्र हीविधार है। चुनाव के समय उमड़ी बोट के कारण नेताजी भी ताप नोड कर उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। अगर किसी तरफ नीति आयोग पर या किसी और बहाने उन्हें बोट से बचाति बिल्कु नहीं तो यह न केकल होता बत्ति आक्रोष करे भी जाम दे सकता है। जैसे मुकेश गुन ने कहा है 'सिस्टम' में खड़ा आम आदमी के लिए बहुत जल्दी है। इसी कारण चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष महापंचांग (एप्रिल-अप्रैल) वर्ष प्रक्रिया जो शुरू की है और जिस तरह की है उसमें बहुत बेचौंडी फैल गई है। कई अमुख्य मताल उठ रहे हैं। 24 जून को अन्यका चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि वह बिहार में महीने मतदाताओं की जून के लिए एसएडीआर शुरू कर रहा है। बिहार में नवम्बर में चुनाव होने हैं। इतने कम समय में वह चुनाव आयोग 8 करोड़ मतदाताओं की सही जांच कर सकता? विशेष तौर पर उस प्रति में जहां से भागी मर्जिला में लोग ज्ञान काम करने जाते हैं? ऐसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिए समय चाहिए, पर बिहार में प्रक्रिया उस समय शुरू की गई जब वहां बहु प्रस्त लोगों को उससे परिवर्तित कर दें थे। वह मताल बहु जद (यू) के समाप्त विशिष्याएं यादव ने भी प्रियकरता की है कि प्रदेश का द्वितीय और भासोल जाने विना चुनाव आयोग ने जबरदस्ती वह प्रक्रिया हम पर थोप दी है। आयोग ने मतदाता मूली में नाम दर्ज करवापे के लिए जो शर्तें रखी वह भी अनोखी हैं। मतदाता को अपनी फहचन बताने के लिए जिन 11 दस्तावेजों में से एक बताना है उनमें आधार कार्ड, बोटर पहचान पत्र या राशन कार्ड नहीं है। अनोखेगिरिक स्थिति है कि विस पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड बहुत नहीं है। उमे तो सबों में रखा गया है, पर आधार कार्ड नहीं है। गनव है कि चुनाव आयोग ने तो उसना पिलाया है, जो उसकी विवरणों में दर्ज है।

79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष: साम्राज्यवाद और भारत के साथ उसकी दादागौरी

Page 25

वह एक्षेन्यानुन ही विश्वास्त्र सामाजिकवाद के लियाकार भासतोंय जाता के संघर्ष की जैत की अद्वलतस्त्री साल्हिंगरा के मौके पर, अमेरिकी सामाजिकवाद भारत को खुल्लमखुल्ला धौम दे रहा है कि उसका फरमान मानना पड़ेगा। बहस्त्राल, यह कहा जा सकता है कि ऐसा करने तो सामाजिकवाद को प्रवृत्ति ही है बास्तव में इन अद्वलतस्त्री सालों के दैरान अमेरिकी सामाजिकवाद ने भारत को अपने फरमानों के लियाव रूप से चलाने की बड़ी कोशिशें की हैं। लेकिन, फूले की इन कोशिशों और वार्मान कोशिश में दो बुनियादी अंतर हैं। फूला, वार्मान कोशिश को इस तरह की भाषा में लैफैट कर पेश नहीं किया जा रहा है कि, 'हम जो कह रहे हैं, खुद अपने लाभ के लिए बही करो।' अब भारत उसमें कहीं ज्यादा बेताग हैं 'हम जो कह रहे हैं, अपने फरवर्द के लिए बही करो, बर्ना तुम्हे सबा दी जाएगी।' दूसरे, उत्तोत में जो लोता आया था उसके विपरीत भारत सरकार अब इसका दो-तृक तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता है बल्कि इस दादियाँ के समाने मिश्रित संकेत दे सकता है। मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ। स्वतंत्र भारत ने जब सीटों (एम्प्रेस्टों) तथा सेंट्रो (सीईपीसीओ) जैसे, सेव गठजोद्यों में से किसी में भी शामिल होने से छुकार कर दिया था, जो अमेरिकी सामाजिकवाद ने सांविधान संघ को बेरने के लिए दुनिया भर में खड़े किए थे और इसके बजाए भारत ने गृहनिषेद्धता की जैति को बुझा था, ताने अमेरिका को नापाजगी मोल लो थी। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्रिव, जॉन फॉस्टर डलाम ने यह मिश्रित पेत किया था 'अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, तो तुम हमारे खिलाफ हो।' इसी के अनुसार अमेरिका ने भारत के साथ राजता का बरताव किया। नियोजन के महत्वकालीन वर्षों के दैरान, जब आत्मनिर्भरता पर, सांघरणिक सेव के तत्कालीन मैं अर्थव्यवस्था का भारी ऊँचों आधार निर्मित करने पर और देश की अर्थव्यवस्था पर विकासित दुर्दिया की पूँजी के लियाजे को हटाने पर जोर दिया जा रहा था, हमें अमेरिका में भी और विश्व बैंक जैसी द्वारा द्वय नियकित यथाओं में भी, शायद ही कोई 'विकास सहजता' मिली थी। अमेरिकी फड़ में संचालित जौ विभिन्न अमेरिकी 'विशेषज्ञ' भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने उस महलमकोम रणनीति को अपनाने खिलाफ 'मलाह' दी थी, जो आत्मनिर्भरता के इस तरह प्राथमिकता दिए जाने को अभिव्यक्ति देती थी। (देखिए, डेमोक्रेट और एनिम थार्म को किसब, लेंड एंड लैबर इन डिड्या में लेख, 'प्लाओइंग द फ्लाम अंडर'। बहस्त्राल, सांविधान संघ के सुनहर ममर्थन

को अपना नामि, दोनों पर छाग रुहा और उसने ऐसा चिना विकसित दीनिया को पूजी के बच्चेव को कट करने के लिए, सर्वव्यापिक शैतान का उभयंग करने के जरूर। उसे किंद्रो मृदु को कड़े राशनिग करनी पड़ी, लेकिन वह अपने गहन पर बना रहा। 1950 के दशक के आखिर में, छोटे को मृत्यु के बाद अमेरिका ने धौर-धौर अपना सुख बदला। उसको उत्ता कि उसको दर सुहृद रहने को जैसी नीतियाँ, भारत जैसे देशों को ज़्यामै का काम करने के बजाए, सुहृद उसे का नुकसान कर रहे थे (और सोवियत संघ को मद्दत कर रहे थे)। पश्चात के दशक के आखिर में अद्यतनवार के भारत के दौर के बाद, आखिरकार विश्व बैंक से कुछ 'सहायता' आनी सुरु हुई और वह भी मिर्ज़ानीयाँ द्वारा गत परियोजनाओं के लिए। पुनर्वालादेश सुहृद के दौरम, जब भारत के इन्सेप ने अमेरिका को ग़ब्बास्त्री का फ़ायदा ठहरने के स्वर्णिम अवसर से बचित कर दिया, उसको समझत तो इन्होंने खुश हो गयी कि उसने अपने विमान वाहक पेट, यूएमएस पंटरेफ़ैन को अगुआई में अपने हाथ पोर्ट 74 को भारत को धैम देने के लिए बांगल को खाली में भेज दिया। बालादेश, अमेरिकी धर्मियों में अकिञ्चन भरत अपने रास्ते पर कायम रख और उसने बालादेश के मिर्गण की प्रक्रिया में मदद की। इस तरह अमेरिकी मास्ट्राइकेट द्वारा दावागीरी चलाया जाना और मिर्ज़ा अपना बच्चेव कायम करने के अप्प मास्ट्राइकवादी उद्यम के तौर पर ही नहीं, लेकिन मालों में भी भारत को अमेरिकी पेंडेंट के लिस्ट से बचाने को कोशिको किया जाना, एक पुणी परिषट्ना है और स्वतंत्र भारत पहले सफलता के साथ इसका प्रतिरोध करता आया था। लेकिन, वर्तमान दावीगोठ, भले ही नवी चीज़ नहीं है, एक मिस्त्रित भिन्न मंदभै में हो रही है, जहाँ देश ने जन-उदास्तवाई पूजीवाद को और इमलिए वैधीकृत वित्तीय पूजों के बच्चेव को अपीकार किया है। लैम्हलैटैप की वर्तमान पीमबाज़ी, जो भारत तक ही सीमित नहीं है, दो मुद्दों को लेकर ही पहला है टैरिफ़ का मुद्दा। इस मामले में 1 अप्रृत तक समझीता नहीं हो पाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिकी बाजारों में भारतीय मालों पर 25 फीसद टैरिफ़ लगेगा। दूसरा मुद्दा दंडनामक टैरिफ़ों का है, जो अमेरिका, भारतीय मालों पर मिर्ज़ा इमलिए लगाने की धमकियाँ दे सकता है कि भारत, रूप के मिलाफ़ पश्चामै द्वारा लगायी गयी परवाइयों का उद्धरण करते हुए, अपने तेज़ सुरक्षिता रहा है। इसके अलावा टैप ने बिक्री को लेकर भी इत्यर्थियाँ की हैं, जो इसका दृश्य है कि वह भारत को इमके लिए धौप्र में लेने का द्वारा रखता है कि वह या तो बिक्री मण्डल को

अमेरिका के एनेट या ट्रैनन हीसे का ब्राम करने की वजह से बाहरील, रूपों तेल खारेदाने के तात्पारिक तथा अनियादि मुद्दे पर भारत सरकार बिन्दु-पराजय करती रही है, और अमेरिका विश्वास की ओर इशारण करते हैं। चूंकि रूपों तेल, अमेरिका द्वारा अनुमोदित, भारत को उत्तरव्य दूसरे सभी देशों से समझा है, यह स्कलान्स्पष्ट है कि भारत को छलकर रूपी तेल खारेदाना बंद करने के लिए अनज्ञान किया जाना, उसे अपने ही हितों के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जाना है। और वह भी कसरिलिए? ये कोई संयुक्त गण संघ द्वारा लगायी गयी आवादिया तो है नहीं, जैसा पार्वदिया मिमाल के तौर पर गोद्वानी द्विषिण अफ्रीका के खिलाफ लगायी गयी थी। ये तो अमेरिका तथा अन्य सामाजिकाने देशों द्वारा अपना हुआ मानने वाले देशों के खिलाफ लगायी गयी पार्वदिया है जैसे कश्युता, इगन या वेनेजुएला के खिलाफ उसको आवादिया। इसलिए, अन्य देशों को धौम डेक ऐसी आवादिया स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, सामाजिकवाद के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने हितों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करना है। दूसरे गोद्वानी में इसका बोर्ड आवरण तक नहीं है कि इन देशों में किसी उच्चतर मिहान के नाम पर, अमेरिका का अनुसरण करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें तो खुब्सखुब्स और आपक तौर पर धौम में लिया जा रहा है, ताकि खुद उनकी विभिन्न पर, सामाजिकवाद के रणनीतिक हितों को आगे लड़ाया जा सके। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर ट्रैप की बात होने से माझमाझीक और निष्ठायक तरहीके में तुकाराया क्यों नहीं? अखिलकार, अगर चीम को छोड़ भी दिया जाए तब उसी जैसे, ज्ञानील जैसे पूजीवादी देश की भी सरकार ने ट्रैप का साधन के साथ जबक दिया है। गणपति लूला ने एलान किया है कि अगर ट्रैप, ज्ञानील के मालों पर 50 फीसद रिफिल लगाएगा, तो ज्ञानील भी अमेरिकी मालों पर 50 फीसद टैरिफ लगा देगा। करियर पार्टी ने तचित ही मोदी की कुनैदिलों को रेखीकृत किया है और उसके मुकाबले में जैसलादा युद्ध के दैशन निवास में इंदिरा गांधी की साहस्रमयक टक्कर को रखा है। (निवास ने एक बार कबूल किया था कि उनकी अग्नों में अखिलकर बात करने में अद्वितीय लगता था।) लेकिन, एक जैता की साहस्रमयकता या अखिलदीली, वर्गीय अधार पर स्थानव नहीं होती है। और लूला और मोदी के बीच यही अंतर है कि जहाँ लूला की जड़ें अजबूर वर्ग के बीच हैं, मोदी को मजबूरी के कुछ बोट भरने के मिलते हैं, वह चुनौतीयी तौर पर बहु पूर्वापति वर्ग के

प्रासादों के स्थानों के प्रति, भारत के हस्त में उब और व यह में जो अंतर है, वह उसना ज्ञाना मोटी बो तुलना में कर तथा इंद्रिय गाथों के लोकिंगत गुणों को प्रियता में लेत नहीं है (हल्दीकि उनके लोकिंगत गुणों के अंतर से और नहीं किया जा सकता है), लेकिन यह अंतर ज्ञानज्ञवाद-विशेषों नियन्त्रणात्मक मिजाम और नव-ज्ञानवादी निजाम के बीच के अंतर में हो जाय निश्चिन्त है।
स्वतं स्पष्ट है कि किसी देश की विदेश नीति और उसके उपर्याख नीति के बीच घनिष्ठ रिश्ता होता है। जहाँ अंतर्ज्ञानात्मक आधिक नीति, जो आत्मनिर्भरता को विस्फुटता देती थी, भारत की गृहीत-प्रणाली की नीति से एक खाती थी और इसलिए, सामाजिकवादी दावोंये वा अभिला करने के लिए उनके तैयार होने से तथा मुकाबला नहीं को उसको समझने में मौल खाती थी, नव-ज्ञानवादी नाम तो आत्मनिर्भरता की किसी भी कोशिश को विफल नहीं में हो गवं करता है। 'मैरु इन इंडिया' विदेशी पूर्जो लिए इसका आमतंज भर है कि यह आकर उपादन। नव-उद्यानवाद का मूल तर्क है, किसी भी ज्ञानसाहित देश का आत्मनिर्भरता की तमाम कोशिशों से हटा है और यह अपरिष्कृत रूप में इन देशों को सामाजिकवादी पौसवानी के सामने वेष्य बना देता है। भारत जब नव-उद्यानवादी निजाम लाया गया था, उसके पांच में दलील थीं जो यहीं कि यह एक स्थायी नवी व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत पूर्जो वैशिष्टक स्तर गतिशील होगी, जिसके चलते विकासशील दुनिया या अबल मानव के कम मनवी वाले देश अब ऐसी अनेक विशिष्ट गतिविधियों का मुख्य ठिक्का बन जाएंगे, जो फलते कमित दुनिया या वैशिष्टक उत्तर में अपना ठिक्का बनाए रखी।

पर में दृष्टिण की ओर इस तरह वह पुनर्संधारण, दृष्टिण में डेंगेम और गरोबी को प्रिय देखा। बहुदल, इस दृष्टिण से एक स्वतंस्पष्ट सामग्र्या यह थी कि किसी वैशिष्टक वस्त्या के संबंध में कुछ भी सदा-सदा के लिए वैष्य कर्त नहीं चला जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएँ ज्ञानवाद द्वारा मढ़ी जाती हैं और जैसाकि अब अस्पष्ट है, सामाजिकवाद उन्हे अपनी मर्जी से कभी भी छल मिलता है। लेकिन, नव सामाजिकवाद ऐसी किसी नुस्खे व्यवस्था में अपने पांच पीछे खीचता है, उसके ज्ञान में पांचे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, खुद उसमें पे मिक्कल पान मुक्किल होता है। जब कोई देश और निर्भर हो जाता है, उसके व्यापार में कोई भी सुलतनी से, उस पर भारी चोट पड़ती है।

मतदाता की नागरिकता

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा मतदाता सूची के गहन पुनरीष्टण का कार्य जभी पूरा नहीं हुआ है बोकांपेर अगमल महीने में मतदाताओं को अपने दाख पेश करने का अधिकार है। चुनाव आयोग 30 सितंबर को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा परन्तु जभी जो उसने फोरे सूची जारी की है उसमें बिहार के कुल सात करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिये गये हैं। देश की विषयों पार्टियां उसके इस फैसले का कहां विरोध कर सकी हैं और कह सकी हैं कि चुनाव आयोग पुनरीष्टण के नाम पर मतदाताओं के नाम काटने का सवान अभियान चला रहा है। विषय के नेता श्री राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह एक नागरिक-एक वाट का भवाल है जिस पर भारत का पूरा लोकतन्त्र टिका हुआ है। विषय का तर्क है कि चुनाव आयोग किसी भी चार्ज की नागरिकता को जांच नहीं कर सकता है। उसे इसका अधिकार संविधान नहीं देता है। संविधान उसे देश में निष्पक्ष व स्वतन्त्र चुनाव चुनावे का अधिकार देता है। इसमें कहीं ठे गय नहीं हो सकती कि चुनाव आयोग को किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को जांच करने का अधिकार नहीं है। किसी भी नये मरुदाता को वह बचन देना पड़ता है कि वह भारत का नागरिक है और उसका बोट बन जाता है। चुनाव आयोग ने इस सन्दर्भ में अपनो शतों में संशोधन किया है और वह नागरिकों से ऐसे प्रपत्र मांग रहा है जिसमें उनकी नागरिकता को पुष्टि होती हो। स्वयंच्व न्यायालय में गहन पुनरीष्टण को लेकर बड़े वाचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनको सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के दौरान अदालत में प्रभावित पाल को आर से तर्क दिया गया कि नागरिकता तथ करने का काम केन्द्रीय मुख्यमन्त्रालय का है। इस तर्क के पाल में न्यायालय में सुनवाई कर रही दी न्यायमतिव्यों को पैठ ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि नागरिकता कानून बनाने का काम

की संसद का है। संसद हो इस बारे में बना सकती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुनाव आयोग किसी भी मतदाता नागरिकता पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करता। ऐसा करने पर वह अपने अधिकार बाहर जाता है। बजौर्कि दूसरी तरफ भारत विधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति वैध वाक्य को बोट देने का अधिकार है। इस हिसाब से उसके घटने के बाहे चलिए परन्तु चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम में हैं उनके सन्दर्भ में जो कामण दिये हैं वे लगते हैं। आयोग का कहना है कि 2003 वार्षि लाखों लोगों ने बिहार लोड कर अन्य को पलायन किया है, लाखों लोग मर चुके लाखों को सख्त्या में ही लोगों के नाम दे पर मतदाता सूची में शामिल हैं। न्यायालय के इन तर्कों को खोकार किया है जो कि रह जायेन लगता है। मगर इसके साथ यह तर्क है कि 2003 के बाद बिहार में कितने लोड बढ़े हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने 2003 में आधार वर्ष माना है। इस वर्ष बिहार में ज्ञान सूची का पुनरीष्टाण किया गया था लेकिन साथ यह सबाल बुद्ध दुआ है कि विगत 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वे मतदाता सूची के आधार पर हुए थे। के नेता कह रहे हैं कि क्या ये चुनाव गलत के आधार पर हुए थे ? इसका जवाब आयोग नहीं दे सकता है। मगर वह कह सकता है कि आधार काढ़ या पुगाने मतदाता पहचान पर आधार पर किसी जायज मतदाता की पहचान नहीं सकती है। उसके इस तर्क को सबौच्च नियम ने सही माना है और कहा है कि दोनों पत्र नागरिकता के प्रमाणपत्र नहीं हैं। यहाँ के गश्न काहूं को भी न्यायालय नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं मान रखा है। निष्कृत रूप से यह भी है कि क्योंकि आधार काहूं पर ही वह

वह नागरिकता का सबूत नहीं है। भारत में फर्जी बना जिसे जाते हैं वनियों में आधार काढ़ का प्रयोग बोटर पहचान पत्र को लेकर भी अतः चुनाव आयोग के तर्कों में न दिखाइ देगा है परन्तु यह सही उब नहीं है क्योंकि साक्षात् कहता है कि चाच करने का अधिकार को ही ही नहीं। उसके सामने किसी यह शपथपत्र ही काफ़ी है कि वह एक है तो यह चुनौती देने वाले का ऐसा सिद्ध करे। भारत में पुस्तों की नागरिकता को चुनौती केवल न होने की वजह से नहीं ये जापीदृश्यों के लोगों के पास न अपना होता था और न कोई स्कूली सरसे आज आयोग ये प्रमाणपत्र उसे जायज किस तरह कहा जाएँ कि विहर के सन्दर्भ में चुनाव के बाद पैदा होने वाले लोगों से मांग रहा है। मगर घूम फिर कर ए पर आती है कि क्या चुनाव सीधी व्याप्ति की नागरिकता तय करने हो। जहाँ तक भारत की चुनाव वाल है तो यह समावेश है न कि एक जिन लोगों को मुख्य हो चुको एक जल्द सूचों से कटने जाएँ। मगर ऐसके आयु लेने पर नाम जुड़ने भी उससे भी कम प्रभाव और सबसे बड़ा क्या चुनाव आयोग को सघन का अधिकार है क्योंकि चुनाव भी कानून में सघन या गहन जिक्र नहीं है ही यह जल्द है कि हर वर्ष चुनाव आयोग पुनरीक्षण जी में संभोधन करता रहेगा। अतः नित के सामने यह भी है।

पौरवारों को सुनिश्चय यह दर्द केवल राजनीति के टृट्टे और सामाजिकों की स्थिती है। उस भ्राताल ने न केवल को भी तोड़ दिया है अती जिजा द्वारा दोनों में भक्ति दिया जिस अमृत 1946 का एक ऐसा कल्पना अवश्य इसमें की मानवीयता तक हिसाने ने न केवल भी प्रथर बना दिया लोग अपनी धर्मों द्वारा तो उम संघर्षों के पैदा हुए कठोरियों में गुज़र दास्तान है जो पौँछा एक ऐसे पिता का है जो आपने आग में डाल देता हुनको इन्हें के राज आठ बच्चे, उनका है जो आख्तों के साथ सुनहरा देती है। उस विस्थापित भारतीय पौत्रों हैं और अपने हुए अत्याचारों को महिलाओं का अपना परिवर्ग ने अपनी नीति समय को पौँछा कर अपमान या जिसने निर्दयता ने मानवीय भूलाना आज भी सही, बाद में सहित सही की 'यमस' जो चिकित्सा किया, विंस्टन की 'ट्रेन टू पार' की कहानी को बढ़े-

विभाजन विभाषिका का दश

1947 स्वतंत्रता का वह सुनहरा जब पूरे देश का प्रभाग भी अनादि की महक फैल रही थी, उसी बढ़क एक अधिक ज्ञासदी भी हमारे दरखाजे पर दसक दे रही थी। भारत के इतिहास में 1947 का साल केवल एक नई शुरुआत का नहीं, बल्कि एक ऐसी विभीषिका का भी था जिसने करोड़ों पौरवारों को सुर्खियां लौट ली और उन्हें वात्स के लिए जरूरी कर दिया। यह दर्द केवल राजनीतिक सीमाओं के बंटवारे का नहीं था, बल्कि मानवता के टूटने और सामाजिक रिश्तों के छिपने का था। जब देश के नक्षे पर लक्षणों की स्थीरीय हुई, तब हजारों निदेशों को जिंदगी में भूचाल आ गया। उस भूचाल ने न केवल धर-बार लैन लिए, बल्कि इंसानियत के उन धारों को भी तोड़ दिया जो सार्टियों से हमारे बीच एकता का आधार था। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत की राजनीति ने देश को उस आग के गर्त में भक्ति दिया जिसकी परिणत्या आज तक हमारे समाज से नहीं गई। 16 अप्रृत 1946 का दृश्योक्त एवस्तन हे भारत के स्वतंत्रता औंदेशन का एक ऐसा कल्पा अध्ययन था, जब कोलकाता में न केवल लिट् बल्कि हर इंसान की मानवीयता को छलनी कर दिया गया। उस दिन से बंगाल, पंजाब तक हिंसा ने न केवल लमीन को लाल किया, बल्कि मनुष्यों के दिलों को भी पश्चात बना दिया। जब हम संचरते हैं कि उस बक करोब 1.5 करोड़ लोग अपने धरती ढोड़ने को मनवार लूए और लगभग दस लाख जने गई, तो उस संघात के पीछे दूरी गमगोन कर्त्तव्यिय हमारे समाज निर्वित होते हैं। इन कहानियों में नुजरायाता के लाला बलवंत लत्ती का परिवार एक ऐसी दास्तान है जो पौँडा को गहराई और मामकोय बलिदान का प्रतीक बन गया। एक ऐसे पिता का चित्र जो अपनों बैटियों को अपने ही हाथों से मौत नी आग में छाल देता है ताकि वे नफरत की उस भोड़ के हँडाले न हो जो उनकी इच्छत के साथ खिलवाड़ करना जाहीर था। प्रभावती और उनके आठ बच्चे, उनका पूरा परिवार, उस समय की भयावहता की ऐसी तस्वीर है जो आंखों के समान धूमती रहती है। ऐसी हजारों कहानियों भारत भर में सुनाई देती है। उस काले दिन को गंज आज भी दिल्ली के छिंगारे के पांचवां विश्वापित धारतीय बांसोनियों में सुनाई देती है, जहाँ बुर्जुग गम के आस पोछते हैं और अपने खोए तुए धर-बास की बातें बाद करते हैं। औरतों पर तुए अत्याचारों को मिनांत बताना भी मुस्किल है। जब करोब 75,000 महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और अमानवीय दोषण हुआ, तो कई परिवारों ने अपनी बैटियों को मौत दे दी ताकि उनका सम्पन्न जन्म रहे। उस समय को पौँडा केवल एक परिवार को नहीं थी, यह उस समाज का अपमान था जिसने महिलाओं को अपना आधार माना। उस समय की निर्देशना ने मानवीय संवेदनाओं को ध्वस्त कर दिया और उस जरूर को भूला ना आज भी संभव नहीं है। यह दर्द केवल घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बाद में साहित्य और सिनेमा में भी इसे गहराई से दर्शाया गया। भीम साहनी की 'उमस' ने विभाजन के भय और संप्रतिविकता की ज्ञासदी को जो विक्रित किया, वह अब भी पहने जाते हों ब्रक्किंग देता है। सुरक्षत मिंह की 'ट्रेन टू पाकिस्तान' ने मानवीय रिश्तों की टूटन और विश्वासशत की कहानी को बड़े संवेदनशील तरीके से ज्यान किया।



नई दिल्ली (ए के चौपाटी) नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी से सरदार इंद्रजीत सिंह, डॉ रत्ननाला और प्रोफेसर रविकांत ने मुलाकात की। इस बैठक में अंग्रेज भारतीय कांग्रेस कमेटी के OBC/SC विभाग के अध्यक्ष डॉ अनिल जेहिंद और यजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। डॉ अनिल जेहिंद, जो हाल ही में कांग्रेस की OBC विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ने राहुल गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात को बाद करते हुए कहा कि यह बैठक एक छंटे से अधिक समय तक चली और उन्हें समाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा नहीं। वह सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले कांग्रेस लोगों को जोड़ने और कांग्रेस जटी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। यजेंद्र पाल गौतम, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी में थे और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अब कांग्रेस की अनुरूपित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति को राहुल गांधी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

नहु दिल्ली । गुरुवार का भारा बारिश ने दिल्ली को तरबतर कर दिया है। कहीं ट्रैफिक जाम तो कहीं बल्जमाव को स्वरे समझे आ रही है। लेकिन इस भारी बारिश में भी पेट को भ्रूंखले लोगों को मरीं से बहुत निकलने के लिए मजबूर कर रही है। भारी बारिश के बीच भी सड़कों पर कोई तिरंगा झंडा बेचकर अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहा है तो कोई सेब बेचकर शाम के खोजन का नुगाढ़ कर रहा है। भारत मण्डपम से कुछ दूर जाने पर अपनी घोड़ी गाड़ी के साथ खड़े आजम खान सेब बेच रहे हैं। वे सोलामपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपर उजाला को जारी कि वे प्रारिदिन अपने घर से सुबह बार बजे ही मैदी चले जाते हैं। वहाँ से ताजे फल खीरीदकर सड़कों पर अपनी घोड़ी गाड़ी समाकर उसी पर सेब बेचते हैं। वे अपने परिवार में कमाने वाले अकेले हैं और किसी का सहारा नहीं है। ऐसे में बारिश से या तेज धूप, ठंड का मौसम हो या तेज लू की गम्भी, वे बाहकर भा अपने घर पर नहीं सूक पाते हैं। उन्हे बाहर निकलकर पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना दी पड़ता है। नोएडा पल्लाई ऑवर के मौजे तिरंगे बना रहे रठन लाल (50 वर्ष) ने बताया कि वे कौन सा काम करते हैं, यह समय तय करता है। वे कभी फल बेच लेते हैं तो कभी फूल-मत्ता। कभी फलों बेचते हैं तो कभी अन्य सामग्री। चूंकि, इस समय स्वतंत्रता दिवस का समय है, इसलिए वे तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस काम में उनका परिवार लग बटाता है। बारिश का मौसम है तो लोग भौंगने से बचने के लिए रेन कोट खरीदते हैं। शायद यही कारण है कि सुमन कुमार सड़कों पर रेनकोट बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के समय रेनकोट बेचने से हर रेनकोट पर उन्हें करीब 20 रुपये बच जाते हैं। इससे उनके परिवार का गुजारा चल जाता है। जब बारिश का समय बीत जाएगा, वे ठंड में पहनने वाले कपड़े बेचने लगते हैं।

65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें

इसी से कह- मंगलवार तक बताएं, क्या कर रहे हैं, आधार को वैध दस्तावेज माना

नई दिल्ली ।

वित्तर में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने गुहवार को सुधीप्रम कोर्ट के समने अपनी दलीलों रखी। चुनाव आयोग ने दलीलों की शुरुआत करते हुए कोर्ट से कह कि इसके पास कठ नियंत्रण लेने के लिए पृष्ठाप सांझा हो। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुधीप्रम कोर्ट में बिला स्वर पर मत, पत्राधान कर चुके या स्थानान्तरित हो चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर सहमति जताई। इसके बाद सुधीप्रम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 19 अगस्त तक मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं को पहचान का खुलासा करने को कहा। कोर्ट ने 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी। सुधीप्रम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण, कारण सहित प्रकाशित करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि



या दूसरे निवासन क्षेत्रों में चले गए हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं छल सकते? इससे पीछे 30 दिनों के भीतर सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं।
चुनाव आयोग की दलील, कोर्ट की मलाह
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मृत्, विस्थापित या स्थानांतरित हुए लोगों के नामों को सूची एनजीटिक दलों के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निपर रहे। मृत्, विस्थापित या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अमनजनन में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेबसाइटों, स्थानों के विस्तरण के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर विचार करें, जहां लोगों जो जनकारी मृत्, विस्थापित या स्थानांतरित साझ़ की जाती है।

राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का हमला, 'वोट चोरी' के ठोस सबूत दें

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को काशीम नेता गहन गांधी और विष्णु के बोट लिस्ट में गढ़बढ़ी और बोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा, 'बोट चोरी' ऐसी गद्द शब्दों का इस्तेमाल कर करेंद्री भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। आयोग ने कहा, ऐसे आरोप लाखों चुनावकारियों की इमानदारी पर भी चोट है। 'एक व्यक्ति, एक बोट' का कानून भारत के पहले आम चुनाव 1951-1952 में ही लागू है। यदि किसी के पास इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी चुनाव में वास्तव में दो बार मतदान किया है, तो उसे बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को 'चोर' कहने के बजाय, एक राष्ट्र-पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को यह प्रमाण सौंपना चाहिए।

बंगाल के बिना भारत को आजा
कोलकाता।

बंगाली भाषा विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुहवार को बढ़ा क्षयन दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। क्योंकि रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हँस्यांगी यहीं पैदा हुई थीं। उन्होंने देश के भाग्य को आकार देने में अहम योगदान दिया। कोलकाता में कन्याकुमारी योजना की 12वीं वर्षांठ पर हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल आजा को किरण है। वह विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रान, राष्ट्रीय और जब भी कोई विविधता है तो उसके बीच विविधता है। अप याएं कि सेलुल जेल (पोर्ट ब्लेयर में) के लगभग 70 प्रतिशत के दो बंगाली थे। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी दूसरे स्थान पर थे। ममता बनर्जी का यह क्षयन उनका आया जब टीएमसी बंगाली अस्मिता (गौरव) को लेकर अधियाय चला रहे हैं। साथ ही भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्राविकों के उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है।

विभाजन के बाद जो लोग देश पर आए वे सभी नागरिक ममता बनर्जी ने जनाओं से कहा जिसका कल स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी संस्कृतियों और विभाजनकारी विचारों को त्यागने का आग्रह करती हूँ।

वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे : राहुल

नहीं दिल्ला। काशीम क पूर्व अध्यक्ष गणेश गांधी न बृहस्पतिवार का कर्तव्य 17 अगस्त का वह अपना 'वोटर अधिकार यज्ञ' के अरिये कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ बिहार की घरती से सीधी लड़ाई शुरू करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपथ मुद्दा नहीं बरिक लोकतंत्र, संविधान और गण का निषयिक संश्लेषण है। गणेश गांधी ने अधिकार यज्ञ के सबूत हम बिहार की लड़ाई छेड़ रखे हैं। यह सिर्फ एक नुसारी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के मिट्टित की रूप पूरे देश में माफ-मुश्किल मतदाता मूच्छी - हर नागरिक, उड़ो और इस जनांदेशन वार, वोट चोरों की खार - जनता की जीत, और विषयी गठबंधन 'डिडिया (ईडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लिनेशन अलायंप्स) के कहे अन्य घटक दलों के नेता मतदाता मूच्छों के विरोध गहन पुनर्गठन (एमआईआर) तथा कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यज्ञ' शुरू करेंगे। मामागम से इस यज्ञ की शुरुआत होगी और इसका समाप्ति एक सितंबर को पटना के युतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार लैनी' के साथ होगा। इस जनसभा में 'डिडिया गठबंधन के राष्ट्रीय सत्र के नेता शामिल हो सकते हैं।

न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब माँगा

जम्प कश्मीर का पूर्ण सत्य का दर्जा बहस्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर वस्त्रातिवार को केंद्र से जवाब देने को कहा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी उमर गहीं और नायपूर्ति के विनाद चंद्रन की पीठ ने केंद्र को और से परा सलिसिटर बनस्त तुषार मेहता बी दलीलों पर भी गैर किया कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई विचार शामिल हैं।"

सतीश महाना ने की पीएम मोदी की सराहना, कहा - वे एक राजनेता हैं

लखनका। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष मरीश महाना ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरण्हना करते हुए उन्हें राजनेता बताया। विधानसभा मानसन सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को 'विजन-2047' को लेकर नागी चर्चा के दौरान महाना ने मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मैं उनका (मोदी) और मुख्यमंत्री जी का आभिनन्दन करता हूं। महाना ने कहा, जो राजनीतिक नेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं वे राजनेता होते हैं। देश और समाज को शिखर पर पहुंचाते हैं, वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री राजनेता हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जो इस दिशा में सोचते हैं और कार्य करते हैं। महाना ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विकसित भारत को परिकल्पना की है। मैं उनका और मुख्यमंत्री जी का आभिनन्दन करता हूं। मोदी का विजन है कि 2047 तक राम सत्य स्वापित हो।

बंगाल के बिना भारत को आजादी नहीं मिलती, बंगाली भाषा विवाद के बीच ममता बनर्जी का बयान

कोलकाता १

बंगाली भाषा विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजी ने गुरुवार को बढ़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। क्योंकि रवीदानाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी ही स्तरपा यहीं पैदा हुई थीं। उन्होंने देश के धार्य को आकार देने में अहम योगदान दिया। कोलकाता में कन्याकुमारी जौना की 12वीं वर्षिंठ पर हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल आजा को किरण है। वह विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। ममता बनजी ने कहा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीयता और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के लिए बंगाली थे। 70 प्रतिशत के दो बंगाली थे। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी दूसरे स्थान पर थे। ममता बनजी का यह बयान उनके आया जब टीएमसी बंगाल अस्सी (गैरव) को लेकर अभियान चला रही है। साथ ही भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के डल्पोड़न का आरोप लगा रहा है।

विभाजन के बाद जो लोग देश में आए वे सभी नागरिक ममता बनजी ने हाताओं से कहा कि कल स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी संसदीयता और विभाजनकारी विचारों को ल्याने का आग्रह करती हूँ।

A group of school children in uniform are gathered around a small podium. On the podium is a portrait of Mahatma Gandhi. The children appear to be participating in a ceremony or a special assembly.

केंद्र सरकार पर बोला हमला सीएम ममता बनजी ने कहा कि बंगाल को केंद्र से बजट नहीं मिल सकता है। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। यूनाईटेड ने शाख गतिविधियों को फढ़ देना लगभग बंद कर दिया है। राज्य सरकार अब उन राष्ट्रीयिक प्रयासों को प्रश्नोन्तर कर रही है। सीएम ने कहा कि अग्रजी मैट्रिक कढ़ भाषण सोसाइटी की जस्ती है, लेकिन मानवभाषा को नहीं भूलना चाहिए। बंगाली की मिशन सर्वत्याक्षी है।

द्वितीय बाल विवाह को रोकना है औ अगले साल यह मंगलुरा एक करोड़ के पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल विहारी सस्कार ने इस योजना के नियन्त्रण पर 17,000 करोड़ रुपये सुन्दर किए हैं। उन्होंने कहा कि कन्याश्री के कारण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर सून्य है। सस्कार का द्वितीय योवाओं का आत्मनिभर बनाना और उन्हें अपने पिता पर नहाता होने में मदद करना है कन्याश्री योजना के तहत 13 से 18 वर्ष की आगे वर्ग की गणित स्कूलों छोड़ाओं को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये तथा व्यस्क होने पर 25,000 रुपये

